RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 30 OCTOBER TO 05 NOVEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 10 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग का नया तरीका ढूंढा Page 2

नोटबंदी जैसा एक और 'बड़ा कदम' उठाने की तैयारी में मोदी सरकार Page 3

बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो रहे सस्ते ई-रिक्शा Page 7

editoria!

भरे हुए भंडार और भूखा भारत

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में और ज्यादा अनाज रखने की गुंजाइश नहीं है, अतएव फालतू खाद्यान्नों को बतौर मानवीय सहायता एवं दान जरूरतमंद और पात्र देशों तक पहुंचाया जा सकता है। यह पत्र जब लिखा जा रहा था तब ही आंकड़े बता रहे थे, कि अपने ही देश भारत में 6 से 8 माह के शिशुओं में लगभग 90 प्रतिशत कुपोषण के शिकार हैं ।देश में प्रत्येक एक सेकेंड कोई न कोई एक बच्चा कुपोषित हो रहा है। तो यह अनाज विदेश क्यों? क्या भारत के नागरिक मानव नहीं है, या सरकार का मानवीयता का पैमाना बदल गया है। उपलब्ध आंकडें कहते हैं कि 1 अक्तूबर, 2019 के दिन कुल जनसंख्या के हिसाब से देश को 3307.70 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रीय खाद्य निगम के गोदाम एक महीने पहले ही 1 सितंबर के दिन दुगनी से अधिक सामग्री 669.15 लाख टन गेहूं-चावल से अटे पड़े थे। तिअभी खरीफ फसल में धान लहलहा रही है, आने वाले कुछ हफ्तों में केंद्रीय पूल की खाद्य भंडारण सामर्थ्य पर और ज्यादा बोझ पड़ने की पूरी उम्मीद है। फलों और सब्जियों की फसल ने कीर्तिमान कर दिया है, दूध का उत्पादन अलग से 176 मिलियन टन को पार कर गया है। खाने-पीने की इतनी बहुतायत के चलते अब कोई कारण नहीं है जिससे भारत में विश्वभर में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार मौजूद हों। फिर गडबडी कहाँ है? फालतू अनाज का इतना विशाल भंडार होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक में भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों से भी नीचे आ गया है। वर्ष 2006 से शुरू होकर, जब से अंतरराष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक जारी होने शुरू होने हुए हैं, तब से आई 14 रिपोर्टों में भारत की स्थिति सुधरी नहीं है। सारे सवाल प्राथमिकताओं के हैं, सरकार का सारा ध्यान आर्थिक विकास की ऊंची दर पाने पर लगा है , भूख और कुपोषण को आर्थिक उन्नति की चमक ने प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया है। सवाल यह है कि आर्थिक उन्नति होने से भूख कम हो जाएगी ? नही, शिकार जनसंख्या खुद-ब-खुद घट जाएगी। वैसे यह तब भी हुआ था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुपोषण को एक 'राष्ट्रीय शर्म' कहा था। उनसे पहले रहे प्रधानमंत्रियों ने भी समय-समय पर भुखमरी से लड़ने का संकल्प दोहराया था, लेकिन भूख और कुपोषण का भारत में कोई अंत नहीं हैं। भुखमरी हटाना वाकई एक जटिल कार्य है। वैसे भी भारत में नीतियां ज्यादातर खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित होती हैं, परंतु फालतू अनाज को कमी वाले क्षेत्र में बांटना एवं किसानों की भलाई प्राथमिकता पर कहीं दिखाई न देती है, तो सिर्फ चुनाव में। कृषि का पुनरुत्थान करना मूल सिद्धांत होना चाहिए। जो सिर्फ लालीपाप की तरह दोहराया जाता है। क्या इस परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष अधिक होते खाद्यान्न उत्पादन और आर्थिक नीतियों को नए सिरे से निर्धारित करने जरूरत नहीं है? इसके लक्ष्य पुनर्निर्धारित करने के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, यही भुखमरी को मिटा सकती है। कृषि, कृषक, कृषि उत्पादन, नीयत और नीति का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, इसके अभाव में भूख बढ़ेगी और तब उस विकास का हम क्या करेंगे जिससे पेट की आग भी न बुझ सके। पेट की आग से धधकते दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए। कृषि, कृषक, उत्पादन का सही वितरण और भूख को केंद्र में रख कर एक राष्ट्रीय नीति की तुरंत जरूरत है।

धुली और कटी हुई प्लास्टिक बोतलों के कचरे के आयात पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्लास्टिक कचरे के बोझ (Burden) को कम करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धुली और कटी हुई प्लास्टिक बॉटल्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश भर में प्रतिदिन 15 हजार 342 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 6 हजार टन कचरा एकत्रित भी नहीं हो पाता है और इधर.उधर बिखर जाता है। 2018-19 की पहली तिमाही में ही भारत ने 25 हजार मीट्रिक टन प्लास्टिक का आयात कर चुका है। इस दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 24 अक्टुबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीईटी बाटल फ्लैक्स जिसे उपयोग किए गए बोटल से बनाया गया हो को भी प्रतिबंध की सूची में जोड दिया है। पहले इसमें पीईटी बोटल स्क्रेप को प्रतिबंधित किया गया था। इस स्थिती में उपयोग की गई बोटलों को कटी और धुली फ्लैक्स के रूप में बदल कर आयात किया जा रहा था। जोकि उपयोग हो चुकी बोटलों से ही बनता था।

देश में तकरीबन 9 हजार 983 मीट्रिक टन कचरा जयपुर आईसीडी. कनकपुरा के जरिए आयात हुआ था। गैर-सरकारी संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समिति की ओर से दिए गए आयात आंकड़ों ने इस प्रतिबंध में अहम भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिसाइकिलर्स और कपड़ा उद्योग अनैतिक रूप से प्लास्टिक बॉटल्स के कचरे को फ्लैक्स के रूप में पाकिस्तान बंगलादेश एवं अन्य देशों से आयात कर रहे थे, क्योंकि यह रीसाइक्लिंग के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्लास्टिक कचरे को इकठ्टा करने की तुलना में सस्ता था। मंत्रालय के खतरनाक पदार्थ प्रबंधन विभाग ने इसी माह इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच और स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के भतीजे ने विनोद शुक्ला ने बताया इम्पोर्ट सिस्टम में एक खामी (लूपहोल) के चलते भारतीय कंपनियां पेट बोतलों के कचरे को आयत एवं पुनःचक्रित करके विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग करते थे। वे हर साल पीईटी बोतलों को रिसाइकिल करके सैंकड़ो तरह के उत्पाद जैसे; पॉलिस्टर कारपेट, टीशर्ट, एथलेटिक जूते, सामान, औद्योगिक स्ट्रैपिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स फ्यूज बॉक्स, बंपर और डोर पैनल आदि का निर्माण कर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मुनाफा कमाने वाले इन उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वे प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग में स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्लास्टिक (पेट) कचरे को इकठ्टा करें और उसका उपयोग करें, जिससे उनका व्यापार सुचारू रहे और और देश को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में भी मदद कर सकें।

हम पीईटी बोतलों को रीसाइकल के लिए आयात करने के खिलाफ

उन्होंने कहा हम पीईटी बोतलों को रीसाइकल के लिए आयात करने के खिलाफ हैं, क्योंकि जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक कोई भी घरेलू प्लास्टिक कचरे को नहीं खरीदेगा, ना ही एकत्रित करेगा। जबकि हमारी प्राथमिकता समस्त घरेलू प्लास्टिक कचरे का रीसाइकल में होनी चाहिए। यदि इसका अधिक आयात होता है, तो सड़कों पर प्लास्टिक कचरे का और बड़ा ढेर लग जाएगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शुक्ला ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात करए प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आयातित प्लास्टिक कचरे को दी गई प्राथमिकता, डोमेस्टिक सप्लाई चेन के टूटने का कारण बनेगी। साथ ही प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने वाले हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित भी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे ना सिर्फ हमारे प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने का कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि ऐसे हजारों परिवार जिनकी एकमात्र आजीविका का साधन यही है। उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है।

नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद

शुक्ला ने यह भी बताया कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा में मंत्रालय के इस निर्णय की सराहना करते हैं। प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए बड़ी संख्या में मानव शक्ति की जरूरत है, जो अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइकलिंग उद्योग में भारत भर में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। पीडीयूएसएम ने पर्यावरण मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले कुछ महीनों में कई बार फ्लैक्स एवं लम्प्स के आयात प्रतिबंध पर चर्चा की। भारत ने अप्रैल2018 से फरवरी2019 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया गणराज्य और अमेरिका आदि जैसे देशों से 99,545 एमटी प्लास्टिक के गुच्छे और 21,801 एमटी प्लास्टिक की गांठ का आयात किया था। जिसमें से 55,000 टन संयुक्त रूप से केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से था। बता दें कि भारत दुनिया में ना केवल प्लास्टिक के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। बल्कि विश्व स्तर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करने वाले देश में सबसे आगे है। भारत में लगभग आधे प्लास्टिक कचरे का ही रीसाइकल किया जाता है। शेष भाग, सड़कों पर, कचरे के ढेरों के रूप में, और जल निकायों में जमा होता रहता है। यही कारण है कि देश में प्लास्टिक के कचरों के कई पहाड़ खड़े हो चुके हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगी कि हम अपने पैदा किए गए कचरे को ठीक से रीसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। मगर फिर भी हम दूसरों देशों के प्लास्टिक कचरे को आयात कर रहे हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग का नया तरीका ढूंढा; इससे मोटर ऑयल और कॉस्मेटिक्स बनेंगे

न्यूयॉर्क। एजेंसी

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का नया तरीका ढूंढ़ निकाला है। इसके जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक को अच्छी क्वालिटी के तरल पदार्थ में तब्दील कर इससे मोटर ऑयल, लुब्रीकेंट्स, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से मौजूदा रिसाइकिलिंग के तरीकों में भी सुधार होगा जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। रिसाइकिलिंग का यह तरीका नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दो अन्य लैब के साथ की गई संयुक्त रिसर्च में निकाला है। यह शोध एसीएस सेंट्रल साइंस में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिक पहले जब प्लास्टिक को रिसाइकिल करते थे तो उससे जहरीली गैस और पदार्थ बनते थे, लेकिन नए प्रयोग में उत्प्रेरक को शामिल कर प्लास्टिक गलाने से बहुत कम जहरीली गैस और खराब पदार्थ निकलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से भारत समेत तमाम ऐसे देश को ज्यादा लाभ होगा, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत ज्यादा है और अपशिष्ट के मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है।

देश में रोजाना 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रो. केनेथ पोपेलमीयर ने कहा- 'इस नई तकनीक की खोज से हम इसलिए खुश हैं क्योंकि दुनियाभर में जमा हो रहे प्लास्टिक के कचरे से लोगों को मुक्ति मिलेगी। प्लास्टिक को हम पिघला सकते हैं खत्म नहीं कर सकते। हमारी नई खोज पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं है।' इधर, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक देश के 60 बड़े शहरों से रोजाना 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है।

सिर्फ 60% प्लास्टिक कचरा रिसाइकल होता है

देशभर से रोजाना 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें से सिर्फ 60% यानी 15,384 टन प्लास्टिक कचरा ही एकत्रित या रिसाइकल किया जाता है। बाकी नदी-नालों के जरिए समुद्र में चला जाता है या फिर उसे जानवर खा लेते हैं। हर साल 1.5 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा विदेशों से भारत आता है। इसी साल अप्रैल तक 19,305 टन कचरा विदेशों से आ चुका है।

हर भारतीय सालाना 11 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है : रिपोर्ट

फिक्की की हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर व्यक्ति सालाना 11 किलोग्राम प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। अमेरिका में इससे 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल

होता है। वहां हर व्यक्ति सालाना 109 किलोग्राम प्लास्टिक प्रयोग करता है। भारत में तकरीबन 5.5 लाख टन प्लास्टिक नदी-नालों से होते हुए समुद्र में मिल जाता है। यही स्थिति रही तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैरता दिखेगा।

आरामको बाजार में सूचीबद्ध होगी, 4 दिसंबर को आएगा आईपीओ

दुबई। एजेंसी

सउदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी सउदी आरामको अपने बहुप्रतीक्षित आरम्भिक सार्वजनिक निर्गम के साथ बाजार में उतरने के बाद 11 दिसंबर को सूचीबद्ध होगी। सउदी अरब के अल-अरबिया टेलीविजन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरामको के आईपीओ के लिए अभिदान चार दिसंबर 2019 को शुरू होगा। इस दिन से निवेशक कंपनी के शेयरों में खरीदारी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद 11 दिसंबर से शेयर की ट्रेडिंग होगी।

मनोज जैन होंगे गेल के चेयरमैन

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने गेल (इंडिया) लि. का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के लिए कंपनी के ही निदेशक मनोज जैन का चयन किया है। जैन इस समय निदेशक (कारोबार विकास) हैं। पीईएसबी की अधिसूचना के अनुसार जैन का चयन देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी के प्रमुख के रूप में किया गया है। पीईएसबी ने आठ छांटे गए उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद महारत्न कंपनी के प्रमुख के रूप में जैन का चयन किया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अब जैन (57) की नियुक्ति का अनुमोदन करेगी। जैन का कार्यकाल अगस्त, 2022 तक होगा। पीईएसबी के नोटिस में कहा गया है कि जिन आठ उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया उनमें गेल के निदेशक वित्त अंजनी कुमार तिवारी तथा इंद्रप्रस्थ गैस लि. के प्रबंध निदेशक ई एस रंगनाथन भी शामिल हैं। इनके अलावा पीईएसबी ने शुक्रवार को दो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों मनोज कुमार (त्रिपुरा के अतिरिक्त मुख्य सचिव) और ज्योति कलश, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगालैंड का भी साक्षात्कार लिया। जैन गेल में अब भुवन चंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। त्रिपाठी को इस साल जुलाई में तीसरा विस्तार नहीं दिया गया था। अभी निदेशक (परियोजना) ए कर्नाटक गेल के कार्यवाहक चेयरमैन हैं।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना को केंद्र से पर्यावरण मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोच्चि में 819 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कोच्चि जल मेट्रो परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना का लक्ष्य कोच्चि के आसपास के द्वीपों को मुख्यभूमि से जोड़ना है। पर्यावरण मंत्रालय की आकलन समिति के इस प्रस्तावित परियोजना पर गौर करने के बाद मंत्रालय ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड केंद्र और केरल सरकार का संयुक्त उपक्रम है। प्रस्तावित परियोजना को अमलीजामा पहनाने का काम इसे ही करना है। प्रस्ताव के अनुसार 15 मार्ग इस परियोजना के दायरे में आएंगे जो कोच्चि के आसपास 78.2 किलोमीटर के जल क्षेत्र में फैले 10 द्वीपों और 38 टर्मिनलों को जोड़ेंगे। प्रस्तावित परियोजना के तहत सात अतिरिक्त टर्मिनल इंफो पार्क, वादुतला, नजराकल, मुलावुकुण व्यू पॉइंट और एंबारकेशन इत्यादि विकसित किए जाएंगे।

शेयर बाजारः सेंसेक्स 40 हजार के पार, जून के बाद पार की ये ऊंचाई

मुंबई। एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को फिर शुरुआती कारोबार में तेजी का माहौल बना रहा और सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले बढ़त बनाते हुए 40 हजार

के मनोवैज्ञानिक स्तर के उपर खुला। निफ्टी भी जबरदस्त तेजी के साथ 11,880 से ऊपर खुला। कुछ घरेलू कंपनियों की बीती तिमाही के मजबूत वित्तीय नतीजों से शेयर बाजार में तेजी का रुझान बना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.30 बजे पिछले सत्र से 110.86 अंकों यानी 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ 39,942.70 पर कारोबार कर रहा था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख सूचकांक निफ्टी 37.45 अंकों यानी 0.32 फीसदी की बढ़त के साथ 11,824.30 पर बना हुआ था। इससे पहले सेंसेक्स 40,055.63 पर खुला और 40,100.26 तक चढ़ा जबकि शुरूआती आधे घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 39,920.67 रहा। पिछले सत्र में सेंसेक्स 39,831.84 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी पिछले सत्र से तकरीबन 100 अंकों की बढ़त के साथ 11,883.90 पर खुला और 11,883.95 तक चढ़ा। आरंभिक कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,816.90 रहा जबकि पिछले सत्र में निफ्टी 11,786.85 पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 582 अंक ऊपर

देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 581.64 अंकों की तेजी के साथ 39,831.84 पर और निफ्टी 159.70 अंकों की तेजी के साथ 11,786.85 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 43.29 अंकों की तेजी के साथ 39,293.49 पर खुला और 581.64 अंकों या 1.48 फीसदी तेजी के साथ 39,831.84 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 39,917.01 के ऊपरी और 39,254.12 के निचले स्तर को छुआ।

इजरायल ने बनाया पानी-ऐल्कॉहॉल से चलने वाला पिस्टन इंजन, पेट्रोल-डीजल की टेंशन हो सकती है खत्म

नई दिल्ली। एजेंसी

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दुनियाभर में बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत को सीमित किया जाए और दुनिया पलूशन फ्री ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। इसी बीच इजरायल में इंजिनियरों की टीम ने एक ऐसा रास्ता निकाला है, जो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल-डीजल की टेंशन को खत्म कर सकता है। इस टीम ने एक खास इंजन प्रोटोटाइप बनाया है, जो एथनॉल के साथ पानी से चलता है। खास बात यह है कि इस इंजन से चलने वाली गाड़ी कम प्रदूषण करेगी और माइलेज भी ज्यादा मिलेगा।

इस इंजन प्रोटोटाइप को MayMaan Research LLC नाम की कंपनी ने डिवेलप किया है। यह एक पारंपरिक पिस्टन इंजन है, जो 70 पर्सेंट पानी और 30 पर्सेंट एथनॉल या किसी अन्य प्रकार के ऐल्कॉहॉल के कॉम्बिनेशन पर चलता है। इस इंजन के लिए डीजल या पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, यानी पेट्रोल-डीजल की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। कंपनी का कहना है कि इससे भी खास बात यह है कि किसी भी कार के इंजन में साधारण मॉडिफिकेशन करके इसे पानी-एथनॉल से चलने वाला बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च बचेगा, बल्कि पलूशन भी बहुत कम होगा। मेमान रिसर्च ने चार प्रोटोटाइप बनाए हैं, जिनमें एक पूरी तरह फंक्शनल कार, एक पावर जेनरेटर और दो अन्य प्रकार के इंजन शामिल हैं। ये इंजन पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ अच्छी मात्रा में टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम हैं।

इंजन को चलाने का खर्च बहुत कम

मेमान का यह इंजन लगभग सभी सल्फर ऑक्साइड (SOx) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के उत्सर्जन को समाप्त कर देता है, जो प्रदूषण करने के लिए जाने जाते हैं। कंपनी का दावा है कि पेट्रोल-डीजल समेत किसी भी अन्य एनर्जी सलूशन की तुलना में इस इंजन को चलाने का खर्च बहुत कम है।

मेन स्ट्रीम गाड़ियों में इस इंजन को आने में लगेगा समय

इस खास इंजन को बनाने वाली टीम के एक इंजिनियर का कहना है कि मेन स्ट्रीम गाड़ियों में यह इंजन आने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर फोकस कर रही है। ऐसे में इस इंजन टेक्नॉलजी को आम लोगों की इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों में आने में समय लगेगा।

शेयर बाजार में निवेश पर टैक्स राहत दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार शेयर बाजार निवेशकों को कर छूट देने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय मिलकर एक ऐसी कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं जिसमें शेयर निवेश पर लगने वाले टैक्स बोझ को कम कर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के समान लाया जाएगा। शेयर बाजार में अभी लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर , छोटी अवधि का पूंजीगत लाभ , सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसआईटी) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) लगता है। वित्त मंत्रालय इन तीनों टैक्स की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा करते हुए यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां, किस-किस टैक्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, किन टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है या फिर नियमों में किस तरह का बदलाव किया जा सकता है। डीडीटी में कटौती को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (डीईए) और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीडीटी को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है।

बजट से पहले ऐलान संभव - शेयर बाजार निवेशकों को कर छूट देने की घोषणा बजट से पहले हो सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बजट से पहले ही इन उपायों का ऐलान कर सकती है।

निवेशक नाराज - इक्विटी के साथ ही सिक्युरिटीज (प्रतिभूति) की खरीद-बिक्री पर एसटीटी चार्ज किया जाता है। निवेशक एसटीटी में कमी करने या इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इससे सरकार को भारी आमदनी होती है। साल 2004 में कैपिटल गेंस को खत्म करने के बाद इसे लागू किया गया था। बायबैक पर लगाया गया 20% टैक्स से भी निवेशक नाराज हैं।

दो महीने से चल रहा काम

वित्त मंत्रालय शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले कर की समीक्षा पिछले दो महीने से कर रहा था। अब अधिकारियों का एक समूह इस पूरे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिर तक इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद पीएमओ से मंजूरी मिलते ही इसका ऐलान किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार के समान कर

सरकार की योजना शेयर बाजार निवेशकों को कर राहत देकर अंतरराष्ट्रीय बाजार के समान कर की दर करने की है। अभी कई देशों के बाजार के मुकाबले भारतीय बाजार में कर की दर अधिक है। इससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में समस्या आ रही है। कर की दर कम करने से निवेशक भारतीय बाजार की ओर तेजी से रुख करेंगे। इससे कंपनियों को पैसा जुटाना आसान होगा।

SBI का मुनाफा तीन गुना बढ़कर 3,011 करोड़ रुपये, एनपीए भी घटा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के सबसे बडे ,सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में स्टैंडअलोन (एकल) मुनाफा लगभग तीन गुना बढ़कर 3,011.73 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 944.87 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। कुल कर्ज की तुलना में बैड लोन (शुद्ध एनपीए) घटकर 2.79% रह गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 4.84% था। धनतेरस के दिन शुक्रवार को कंपनी के शेयर 7.19% उछाल के साथ 281.60 रुपये पर पहुंच गया। एसबीआई का शेयर शुक्रवार को 7.19% चढ़ गया। बंबई शेयर बाजार में बैंक का शेयर 7.19% की बढ़त के साथ 281.60 रुपये पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 8.10% की बढ़त के साथ 284 रुपये पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक का शेयर 7.56% की बढ़त के साथ 282.35 रुपये पर पहुंच गया। बैंक के शेयरों में जोरदार तेजी के बीच उसका बाजार पूंजीकरण 16,868.06 करोड़ रुपये बढ़कर 2,51,317.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।दूसरी तिमाही में बैंक की कुल आय 3ङ्क बढ़कर 72,850.78 करोड़ रुपये रही, जो अप्रैल-जून तिमाही में 70,653.23 करोड़ रुपये रही थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक की असेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और 30 सितंबर, 2019 को ग्रॉस (सकल) एनपीए घटकर सकल कर्ज के 7.19% पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 9.95% था।

नोटबंदी जैसा एक और 'बड़ा कदम' उठाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार एक बार फिर नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस बार नोट बंद नहीं होंगे परंतु कालेधन पर लगाम कसने के लिए लोगों से उनके पास मौजूद सोने का हिसाब मांगा जा सकता है।

समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, काला धन से सोना खरीदने वालों पर लगाम लगाने के सरकार खास स्कीम लाने की तैयारी में है। चैनल ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम ला सकती है। इसके तहत एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले सोने की जानकारी देनी सरकार को देनी होगी। साथ ही सोने की कीमत का खुलासा भी करना होगा।

इस स्कीम के तहत सोने की कीमत तय करने के लिए वैल्युएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर रसीद वाले जितने सोने का खुलासा करेंगे उस पर एक तय मात्रा में टैक्स देना होगा। ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज्यादा सोना पाए जाने पर भारी जुर्माना लगेगा। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर इस स्कीम का मसौदा तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है। जल्द कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल सकती है।

खरीदते और बेचते समय लगता है टैक्स

सोना एक ऐसी कीमती धातु है, जिसे खरीदने और बेचने समय हमें टैक्स चुकाना पड़ता है। सोना खरीदने के 36 माह के भीतर आप इसे बेचते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स लगता है, वहीं 36 माह बाद इसे बेचने पर लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स देना होता है।

सोने की बढ़ती कीमतों पर कसेगा शिकंजा : बाजार विश्लेषकों के अनुसार भू-राजनीतिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की सतत खरीद और रुपए की विनिमय दर की कमजोरी से सोना इस साल के अंत तक 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। बहरहाल सरकार के इस कदम से देश में सोने के दाम गिरने की भी संभावना है।

अक्टूबर में UPI से 1 अरब ट्रांजैक्शन

जल्द विदेशों में भी कर पाएंगे पेमेंट

नई दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार के डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के अभियान को अक्टूबर महीने में जबरदस्त सफलता मिली है। यह महीना फेस्टिव सीजन की शुरुआत को लेकर जाना जाता है। इस बार इस महीने में धनतेरस से लेकर दिवाली तक के त्योहार थे। अक्टूबर महीने में अब तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए एक अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने फेस्टिव सीजन के दौरान खरीद में डिजिटल पेमेंट करने को तवज्जो दिया। तीन साल पहले यूपीआई को लॉन्च किया गया था और अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई सबसे तेजी से बढ़ने वाला सिस्टम बन गया है।

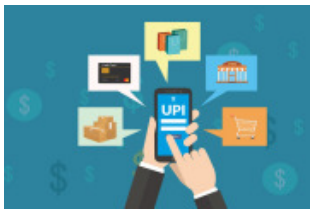

विदेशों में भी कर पाएंगे पेमेंट

सूत्रों ने बताया है कि अब लोग जल्द ही यूपीआई सिस्टम के जरिए विदेश में पेमेंट कर सकेंगे। इस पर नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इसकी शुरुआत सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगी। यहां पर रुपे कार्ड की पहले ही शुरुआत हो चुकी है। दरअसल, आरबीआई की डिजिटल पेमेंट पर नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने सलाह दी थी कि नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भारत के बाहर रुपे कार्ड और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम का विस्तार करना चाहिए।

फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी UPI सिस्टम में

फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां यूपीआई पेमेंट सिस्टम में आ गई हैं। यूपीआई फंड ट्रांसफर की एक प्रकार की सुविधा है। इसके चलते स्मार्ट फोन के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। यह इंटरनेट फंड ट्रांसफर के मेकनिजम पर आधारित है।

खाद्य तेलों के सस्ते आयात के चलते तिलहन उत्पादक किसानों को नहीं मिल पा रहा है उचित मूल्यः उद्योग

नयी दिल्ली। एजेंसी

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने तथा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के घोषित लक्ष्य के बाद भी उद्योग जगत का कहना है कि तेलों के सस्ते आयात के चलते तिलहन किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य न मिलने से परेशान हैं। तेल उद्योग के लोगों का कहना है कि खाद्य तेलों के सस्ते आयात की वजह से सरसों, मूंगफली और सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनके तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तक उपलब्ध हो पाना मुश्किल बना हुआ है। सरकार ने पिछले साल की सरसों का एमएसपी 4,200 रुपये क्विंटल रखा था लेकिन सूत्रों ने बताया कि थोक बाजार में इसके भाव कभी भी 4,000 रुपये क्विंटल को पार नहीं कर पाये।

सरकार ने पिछले दिनों रबी मौसम की फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। इसमें गेहूं का समर्थन मूल्य जहां 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल घोषित किया वहीं दालों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई। सरसों का समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़ाकर 4,425 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य तेल उद्योग के मुताबिक सरकार के प्रोत्साहन और तेल- तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के आह्वान के बीच पिछले रबी सत्र में सरसों का करीब 90 लाख टन उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग 11.5 लाख टन सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी एजेंसियों ने खरीदारी की लेकिन खुले बाजार में सरसों समर्थन मूल्य से 200 से 300 रुपये क्विंटल नीचे बिकी।

पंजाब आयल मिल्स एसोसियेसन के अध्यक्ष सुशील जैन ने कहा, ''पिछले खरीफ सत्र में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4,200 रुपये क्विन्टल रहा है मंडी में इसका भाव एमएसपी से लगभग 200-250 रुपये क्विन्टल नीचे रहा। देश में खाद्य तेलों की मांग के मुकाबले लगभग 70 प्रतिशत कमी होने के बावजूद मूंगफली, सोयाबीन और सरसों एमएसपी से 100-400 रुपये क्विन्टल नीचे बिक रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''विगत खरीफ सत्र में मूंगफली का उत्पादन पिछले साल के 30 लाख टन के मुकाबले बढ़कर इस बार 54 लाख टन हो गया लेकिन राजकोट, जूनागढ़ सहित अन्य मंडियों में यह एमएसपी से 300-400 रुपये क्विन्टल नीचे बिक रही है। मूंगफली का एमएसपी खरीफ सत्र में 4,450 रुपये से बढ़ाकर 4,890 रुपये क्विंटल किया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में सोयाबीन 3,700 रुपये क्विंटल के एमएसपी भाव के मुकाबले 300-400 रुपये क्विन्टल नीचे बिकी है।''

दिल्ली वनस्पति तेल संघ के पूर्व महासचिव पुनीत जैन ने कहा, ''जब पामोलीन 55 -60 रुपये किलो के भाव उपलब्ध है तो 90-100 रुपये किलों के भाव सरसों तेल कौन खरीदेगा।'' सरकार को घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिये कच्चे पॉम तेल पर 45 प्रतिशत शुल्क के साथ 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवाकर (जीएसटी) भी लगाना चाहिये। उन्होंने याद दिलाया की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000- 01 में पॉम तेल आयात पर 80 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था।'' तेल कारोबारी अर्पित गुप्ता का कहना है कि देश में यदि तिलहन उत्पादन नहीं बढ़ा तो खल जैसे पशु आहार, मुर्गीदाना की किल्लत हो सकती है। इसका असर दूध उत्पादन, चिकन, अंडे आदि की उपलब्धता पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ''सरकार को तिलहन उत्पादन बढ़ाना है तो उसे सबसे पहले सोयाबीन, रेपसीड सनफ्लावर पर आयात शूल्क को 35 से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर देना चाहिए।

वर्तमान में कच्चे सोयाबीन, रेपसीड पर 35 प्रतिशत और इनके रिफाइंड तेलों पर 45 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लागू है। गुप्ता का कहना है कि इन तेलों में रिफाइंड तेल का आयात नहीं होता है, इसलिये सरकार को इनके कच्चे तेल पर ही आयात शुल्क बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर देना चाहिये ताकि घरेलू उद्योगों को बेहतर समर्थन मिल सके। कच्चे और रिफाइंड तेलों में 10 प्रतिशत अंतर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोयाबीन को रिफाइंड बनाने में मात्र चार प्रतिशत की लागत आती है।''

बुनियादी ढांचा विकसित करने में पांच साल में 1,400 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत रेल परियोजनाओं, हवाईअड्डों, बिजली संयंत्रों, सड़कों और पुलों सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर अगले पांच साल में करीब 1,400 अरब डॉलर खर्च करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात क्षेत्र पर बने वैश्विक मंच 'ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपिसिटी' (जीएफएसईसी) के सम्मेलन में यह बात कही। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधान ने फोरम में कहा कि देश में इस्पात की मांग में काफी वृद्धि हुई है। भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि भारत 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है। ' उन्होंने कहा कि भारत अपने बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर अगले पांच साल में करीब 1,400 अरब डॉलर (99,40,000 करोड़ रुपये) का खर्च करने को प्रतिबद्ध है। प्रधान ने कहा कि यह सब देश में इस्पात की मांग के लिए अच्छा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को 72 किलो प्रति व्यक्ति के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2030 तक 160 किलो प्रति व्यक्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान दो दिन की जापान यात्रा पर हैं। मंत्री ने इस दौरान शुक्रवार को जापान की दिग्गज इस्पात कंपनियों जेएफई स्टील कॉरपोरेशन , निप्पॉन स्टील और दायदो स्टील के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात की और तेल से बढ़ते भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया।

रेलवे की माल ढुलाई आमदनी दूसरी तिमाही में 3,900 करोड़ रुपये घटी, यात्री राजस्व भी घटाः आरटीआई

नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती का असर दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक भारतीय रेल के राजस्व पर भी दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेलवे की यात्री किराये से आमदनी वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 155 करोड़ रुपये और माल ढुलाई से आय 3,901 करोड़ रुपये कम रही। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ।

आरटीआई में हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश में नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से खुलासा हुआ है कि 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यात्री किराये से 13,398.92 करोड़ रुपये की आय हुई थी। यह आय जुलाई-सितंबर तिमाही में गिरकर 13,243.81 करोड़ रुपये रह गई। इसी प्रकार, भारतीय रेल को माल ढुलाई से पहली तिमाही में 29,066.92 करोड़ रुपये की कमाई हुई जो कि दूसरी तिमाही में काफी कम होकर 25,165 करोड़ रुपये रह गई।

टिकटों की बुकिंग भी प्रभावित

आर्थिक सुस्ती की वजह से टिकट की बुकिंग भी प्रभावित हुई। पिछले साल अप्रैल-सितंबर के मुकाबले 2019-20 की इसी अवधि में बुकिंग में 1.27 प्रतिशत की गिरावट आई है। रेलवे ने आर्थिक नरमी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। उसने हाल ही में व्यस्त समय में माल ढुलाई पर अधिभार हटा लिया है और एसी चेयर कार तथा एक्जिक्यूटिव क्लास सिटिंग वाली ट्रेनों के किराए में 25 प्रतिशत छूट की पेशकश की है।

नरमी से निपटने को कई उपाय

इसके अलावा, 30 साल से पुराने डीजल इंजन को हटाने की पहल शुरू करना, ईंधन बिल में कटौती, किराये के अतिरिक्त राजस्व के विकल्प सृजित करना और भूमि को किराये पर देने या बेचने जैसे कदम उठाए हैं। रेलवे बार्ड ने पिछले महीने सभी 17 मंडलों को सुस्ती से निपटने के लिए उपाय करने को कहा है।

ढुलाई में गिरावट चिंता का कारण

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, माल ढुलाई में गिरावट चिंता का कारण है। कोयला खदानों में पानी भरने से कोयला लदान प्रभावित हुआ है, जबकि इस्पात और सीमेंट क्षेत्र आर्थिक सुस्ती की मार झेल रहे हैं। हालांकि, हमने इन नुकसानों को कम करने के लिए उपाय किए हैं और उम्मीद है कि इस समस्या से मजबूत होकर बाहर निकलेंगे।

दिवाली पर आरबीआई ने उतारे 1700 करोड़ के नए नोट

नई दिल्ली। एजेंसी

दिवाली पर रिजर्व बैंक ने 1700 करोड़ रुपए के खरे-खरे नोट बाजार में उतारे हैं। सबसे ज्यादा मांग दस, बीस और पचास के नोटों की है। सौ और पांच सौ के नोटों की खेप सबसे ज्यादा उतारी गई है। हालांकि बैंकों ने नई करेंसी का एक बड़ा हिस्सा अपने खास ग्राहकों को बांट दिया। दिवाली पर पूजन के लिए रिजर्व बैंक ने नई करेंसी जारी की है। करीब 1700 करोड़ की करेंसी में आधा हिस्सा पांच सौ के नोटों का है। चौथाई हिस्सा सौ के नोटों का है। शेष में पचास, बीस और दस के नोट हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस बार बड़े नोटों के उलट छोटे नोटों की मांग ज्यादा है।

शहर में 600 से ज्यादा शाखाओं में नए नोटों की मारामारी रही। लक्ष्मी पूजन के लिए इस बार बैंकों में 20 रुपए के नोट की डिमांड ज्यादा है। वजह इसका नया होना है। 2018 की दिवाली की बात करें तो पूजन में रखने के लिए 10 रुपए के नए नोट की डिमांड ज्यादा थी। आम लोगों को नई करेंसी के दर्शन कम ही नसीब हुए। ज्यादातर बैंकों ने बड़े ग्राहकों के बीच नए नोटों की गड्डियां पहुंचाईं। एटीएम से भी नए नोट बेहद कम निकले।

दिसंबर तक वार्निश वाले नोट भी होंगे आपके हाथ में

बाजार में दिसंबर तक वार्निश वाला नोट आ जाएगा। आरबीआई सबसे पहले सौ का नोट जारी करेगा। यह मौजूदा नोट के मुकाबले दोगुना टिकाऊ होगा। अभी सौ रुपए का नोट औसतन करीब तीन से चार साल चलता है लेकिन वार्निश चढ़े नोट की उम्र करीब दोगुना हो जाएगी यानी करीब सात-आठ साल तक टिका रहेगा। इन्हें पहले ट्रायल के आधार पर जारी किया जाएगा। नए नोट को ज्यादा संभालकर रखने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि नया नोट ना तो जल्दी कटेगा फटेगा, और ना ही पानी में जल्दी गलेगा क्योंकि इस पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा।

पहली बार इंग्लैंड से छपकर आया था एक का नोट

पूरी दुनिया पहले विश्वयुद्ध की आग में झुलस रही थी। तब भारत के रुपए-पैसे ब्रिटिश सरकार छापती थी। चूंकि लड़ाई की वजह से सिक्के ढालने वाले टकसालों की क्षमता सीमित हो चुकी थी, लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने एक रुपए का नोट निकाला। 30 नवंबर 1917 को इंग्लैंड से छपकर आया ये नीले रंग का नोट जल्द ही भारतीय बाजार पर छा गया।

शगुन के लिए एक रुपए का नोट सीमित मात्रा में जारी

इस बार भी दिवाली में बेहद सीमित मात्रा में एक रुपए के नोट जारी किए गए। ये नोट परंपरा निभाने के लिए शगुन के तौर पर छापे गए हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि केवल एक रुपए का नोट ही एकमात्र ऐसी मुद्रा है, जिसपर आरबीआई का अधिकार नहीं होता। ये नोट सीधे सरकार के नियंत्रण में होता है इसीलिए इस पर आरबीआई गवर्नर की जगह वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। दो साल पहले ही एक रुपए का सुंदर सा नोट सौ बरस का हुआ था।

सोशल सिक्यॉरिटी कोड बदलने की तैयारी और 1 साल की नौकरी के बाद मिल सकेगी ग्रैच्युटी!

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार सोशल सिक्यॉरिटी कोड में बदलाव कर सकती है। ग्रैच्युटी पाने के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इस बदलाव के तहत अगर कर्मचारी ने किसी भी कंपनी में एक साल तक काम किया तो वह ग्रैच्युटी पाने का हकदार होगा। अभी ग्रैच्युटी पाने का अधिकार उसी कर्मचारी को मिलता है, जिसने लगातार पांच साल किसी कंपनी में नौकरी की हो और उसके बाद वह नौकरी छोड़ता हो। इसके अलावा एम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम (ईपीएस) में सरकार की 1.16 फीसदी हिस्सेदारी बकरार रह सकती है।

सूत्रों के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार सोशल सिक्यॉरिटी कोड से जुड़ा बिल पेश करने जा रही है। बिल पेश होने से पहले इसमें कई बदलाव किए जा सकते हैं। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि हमने सोशल सिक्यॉरिटी कोड बिल को लेकर इस मामले से संबंधित कई लोगों और संगठनों से बातचीत की है। उनकी सलाह और मांगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।

'नए कोड में मजदूर विरोधी बातें'

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के अनुसार सरकार ने जो सोशल सिक्यॉरिटी कोड बनाया है, उसमें कई बातें मजदूर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से मांग की है कि ग्रैच्युटी के लिए पात्रता को पांच साल से कम कर एक साल किया जाना चाहिए क्योंकि कई संगठनों में 80 प्रतिशत तक कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं।

NPS को पूरी तरह खत्म कर देगी सरकार!

उनका कहना है कि सरकार की ईपीएस में 1.16 प्रतिशत की हिस्सेदारी वापस ली गई है। इसके अलावा सरकार एनपीएस को एक तरह से खत्म करना चाहती है और उसकी जगह नई पेंशन योजना को लागू करना चाहती है, जो ठीक नहीं है। सरकार को तुरंत इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से पुरजोर तरीके से मांग की है कि वह जल्दबाजी में सामाजिक सुरक्षा कोड को लागू न करे।

80% असंगठित सेक्टर कर्मियों की नौकरी स्थायी नहीं

उन्होंने कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी असंगठित सेक्टर में काम करते हैं और 80 फीसदी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं यानी उनकी नौकरी पर्मानेंट नहीं हैं। अगर यह सोशल सिक्यॉरिटी कोड लागू हो गया तो अधिकतर कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं होगा।

कमजोर वैश्विक रुख से कच्चा तेल वायदा एक प्रतिशत टूटा

नयी दिल्ली। कमजोर वैश्विक रुख के अनुरूप कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से बुधवार को कच्चे तेल का वायदा भाव करीब एक प्रतिशत टूटकर 3,924 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चे तेल का नवंबर आपूर्ति वाला अनुबंध 36 रुपये या 0.91 प्रतिशत टूटकर 3,924 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इसमें 19,919 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह कच्चे तेल का दिसंबर आपूर्ति वाला अनुबंध 36 रुपये या 0.9 प्रतिशत के नुकसान से 3,946 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इसमें 822 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख के अनुरूप कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से कच्चे तेल का वायदा भाव नीचे आया। इस बीच, न्यूयॉर्क में ब्रेंट कच्चा तेल 0.42 प्रतिशत के नुकसान से 61.33 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

बजट घटाने का नायाब तरीका

ऑनसाइट हायरिंग पर भारतीय टेक कंपनियों का जोर

मुंबई। एजेंसी

भारतीय टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनियों ने सब-कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट घटाने के लिए अपने इनोवेशन हब और ऑफिस ऑनसाइट पर हायरिंग बढ़ा दी है। इन कंपनियों में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज प्रमुख हैं। इंफोसिस ने पिछले दो सालों में अमेरिका में 10,000 से ज्यादा लोगों को हायर किया है और छह अहम इनोवेशन हब खोले हैं। फिलहाल कंपनी इन हब में एक टैलेंट पिरामिड बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इंफोसिस ने पिछले दो सालों में एच1-बी वीजा पर भी अपनी निर्भरता काफी हद तक कम की है।

स्ट्रैटिजिक हायरिंग पर फोकस

इंफोसिस की प्रतिद्वंद्वी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) भी सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की भारी लागत कम करने के लिए विदेश में स्ट्रैटिजिक हायरिंग पर फोकस कर रही है। विप्रो के अमेरिका स्थित सेंटर में 68 पर्सेंट लोग वहीं के हैं। कंपनी ने कहा, 'हम अपनी ऑनसाइट वर्क फोर्स की ट्रेनिंग और री-स्किलिंग में पर्याप्त निवेश कर रहे हैं।' कंपनी ने कैंपस हायरिंग को भी पहले की तरह जारी रखा है।

पिरामिड स्टाइल से लागत घटाने की कोशिश

इंफोसिस के चीफ फाइनैंशल ऑफिसर नीलांजन रॉय ने बताया, 'हब बनाने के पीछे असल मकसद यह था कि सबसे पहले हब के आस-पास इनोवेशन लैब तैयार किए जाएं, जहां क्लाइंट आ सकें। हम हब में पिरामिड भी बना सकते थे। ऐसे में वहां एक चुनौती नए लोगों यानी फ्रेशर्स को हायर करने की थी। अमेरिका में टैलेंट की कमी को देखते हुए यह सवाल था कि हम कैसे कम्युनिटी कॉलेजों से फ्रेशर्स को हायर कर सकते हैं और एक पिरामिड बना सकते हैं? और वह भी ऐसा पिरामिड, जो लागत घटाने में मदद करे।'

मीडियम टर्म में होगा इस कॉन्सेप्ट का असर

इंफोसिस के एक दूसरे सीनियर एग्जिक्युटिव ने बताया, 'अमेरिका में खुले हब से हमें काफी मदद मिली। बिजनेस के आधार पर सभी रैंकों में हायरिंग हो रही है।' एक पोस्ट-अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस में टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने बताया कि कंपनी की सब-कॉन्ट्रैक्टिंग लागत स्थिर हो गई है। गोपीनाथन ने कहा कि कंपनी ऑनसाइट हायरिंग और इमरजेंसी लेबर पर लागत घटाने की कोशिश कर रही है और इस रणनीति का फायदा मीडियम से लॉन्ग टर्म में दिखेगा।

एंट्री लेवल पर स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ाई गई

ऐनालिस्टों के साथ हाल में एक मुलाकात में गोपीनाथन ने कहा था, 'हम लागत धीरे-धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने विभिन्न भौगोलिक इलाकों में एंट्री-लेवल पर स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ाई है। इससे हम अस्थाई लैटरल हायरिंग को ऑफसेट कर सकते हैं।'

बाहरी कंसल्टेंट्स को हजारों करोड़ का भुगतान

30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही में टीसीएस ने बाहरी कंसल्टेंट्स को फीस के रूप में 3,279 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,194 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2019 में टीसीएस ने बाहरी कंसल्टेंट्स को फीस के रूप में 11,330 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जो इसके पिछले वित्त वर्ष में रू. 8,992 करोड़ रुपये था।

सऊदी अरब वित्तीय सम्मेलन में 15 अरब डॉलर के कारोबारी समझौतों पर हस्ताक्षर

रियाद। एजेंसी

सऊदी अरब के बहुचर्चित वैश्विक वित्तीय सम्मेलन मंगलवार को यहां पहले दिन 15 अरब डॉलर से अधिक के 23 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य देशों के नेता शिरकत करने पहुंचे हैं। 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम' बैनर तले हो रहे इस सम्मेलन को 'मरुभूमि में दावोस' कहा जा रहा है। यह सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की पहल है। युवराज की योजना सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने की है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों पर उसकी निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण 2030 योजना तैयार की गई है। सऊदी अरब जनरल इंवेस्टमेंट अथॉरिटी (एसएजीआईए) ने एक बयान में कहा कि 'सऊदी में निवेश' (इंवेस्ट सऊदी) के तहत रियाद के रिट्ज कार्लटन होटल में सम्मेलन से अलग एक प्रतिबद्ध समारोह में कुल 15 अरब डॉलर मूल्य से अधिक के समझौते हुए। बयान में कहा गया है कि यह समझौते दुनियाभर और में सऊदी अरब की ओर से निवेशकों की दी जाने वाली पेशकश की क्षमता को दिखाते हैं। एसएजीआईए के गवर्नर इब्राहिम अल-ओमार ने कहा, "आज यहां जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए वह (हमारी) अर्थव्यवस्था की ताकत और विविधता को दिखाते हैं। सऊदी अरब महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम से गुजर रहा है और दुनिया इसका संज्ञान ले रही है।" विश्वबैंक की इसी महीने जारी हुई कारोबार सुगमता सूची-2020 में सऊदी अरब की

रैंकिंग 30 स्थान सुधरी है। उन्होंने कहा, "संकेत साफ है, सऊदी अरब ना सिर्फ कारोबार के लिए खुला है, बल्कि यह भविष्य की अर्थव्यवस्था है।" इस तीन दिवसीय सम्मेलन में सरकार, उद्योगपति और वित्त पोषक भाग लेंगे। बैठक में वैश्विक व्यापार और उसकी प्रवृत्ति पर चर्चा के साथ आने वाले दशकों में वैश्विक निवेश परिदृश्य को लेकर अवसर और चुनौतियों पर बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की यात्रा पर सोमवार देर रात रियाद पहुंचे। वह सम्मेलन में 'भारत के लिये आगे क्या'? विषय पर एक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने यात्रा पर रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में कहा, " मैं वहां वैश्विक निवेशकों के लिए देश में बढ़ रहे व्यापार और निवेश अवसरों के बारे में बताऊंगा। देश 2024 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है।" बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार तथा दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। कुशनर सम्मेलन में अमेरिका के भविष्य पर विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारी, केन्या के राष्ट्रपति यूहुरु केन्याता और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन मंच को संबोधित करेंगे। दुनिया के कई देशों के बैंकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश और मनोरंजन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सऊदी अरब ने पिछले महीने कहा था कि वह भारत में तेल-गैस, पेट्रोरसायन, कृषि, खनिज और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में 100 अरब डालर के निवेश के अवसर तलाश रहा है। 2017-18 में दोनों देशों के बीच 27.48 अरब डालर का आपसी व्यापार हुआ था। सऊदी अरब व्यापार में भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदारी है। मंगलवार को जिन 23 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उनमें एसएजीआईए और भवन निर्माण में काम आने वाली ढलाई की गयी सामग्री बनाने वाली कंपनी मॉड्यूलर मिडिल ईस्ट के बीच 70 करोड़ डॉलर का एक समझौता शामिल है। चीन की ऑनलाइल खरीदारी कंपनी फॉरडील और एसएजीआईए के बीच 30 करोड़ डॉलर और लंदन की शिलॉह मिनरल्स और एसएजीआईए के बीच 20 करोड़ डॉलर का भी अहम समझौता भी हुआ है।

जगत की आत्मा सूर्य देव के प्रति श्रद्धा का पर्व

सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि वे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। उनके आलोक को अपनी चेतना में धारण करने से जीवन प्रकाशित हो उठता है। छठ व्रत इन्हीं जीवनदायी सूर्य देव को आभार प्रकट करने का महापर्व है, जिसमें पूरा समाज बिना किसी भेदभाव के साथ सामूहिक रूप से उनकी आराधना करता है।

छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है, जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित करते हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में हम छठ मनाते हैं। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है, जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। 'छठ' शब्द 'षष्ठी' से बना है, जिसका अर्थ 'छह' है, इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला ये त्योहार चार दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है।

छठ पर विशेष

श्री श्री रविशंकर

इसका रहस्य समझते हैं। इस त्योहार में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका अर्थ क्या है? यहां जल देने से सूर्य के पास पहुंच जाएगा? नहीं। इसका दार्शनिक अर्थ है-जीवन और पृथ्वी का आधार सूर्य ही हैं। यह सूर्य को आभार व्यक्त करने की परम्परा है। पहले प्रतिनित्य सूर्य को अर्घ्य देकर सभी पूजा शुरू की जाती थी।

छठ में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जल या आपः (संस्कृत) का एक अर्थ प्रेम भी है। जल प्रेम का प्रतीक भी है। 'आप्त' एक शब्द है, जो 'आपः' से बना है। आप्त का अर्थ है, 'जो बहुत प्रिय हो।'

इसका त्योहार का उद्देश्य सूर्य से अपनेपन और निकटता को महसूस करना है। सूर्य को जल अर्पित करने का अर्थ है कि हम संपूर्ण हृदय से आपके (सूर्य के) आभारी हैं और यह भावना प्रेम से उत्पन्न हुई है।

इसमें दूध से भी अर्घ्य देते हैं। दूध पवित्रता का प्रतीक है। दूध को पानी के साथ अर्पित किया जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारा मन और हृदय दोनों पवित्र बने रहें।

सूर्य इस ग्रह पर सभी आहार का स्रोत है। यह सूर्य ही है, जिसके कारण ऋतुएं और वर्षा आती है। सूर्य इस ग्रह पर जीवन का निर्वाहक हैं। सूर्य के प्रति कृतज्ञता की गहन भावना के साथ प्रसाद बनाया जाता है। सब्जियों, मिठाइयों और विभिन्न खाद्य पदार्थों को सूर्य को यह कहते हुए अर्पित किया जाता है कि 'यह सब आपका है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है।'

सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पूरा परिवार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में उतरता है। जल हथेलियों में रखा जाता है और सूरज को देखते हुए, जल को धीरे-धीरे अर्पित किया जाता है। सुबह और शाम के समय सूर्य को देखने का महत्व पूरे विश्व में बताया गया है और विज्ञान यह मानता है कि यह शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करने के लिए सूर्य आवश्यक हैं। सुबह और शाम के समय सूर्य का अवलोकन करने से शरीर में सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करने में मदद मिलती है। यह बुद्धि को तीक्ष्ण और सबल करता है। कुछ ऐसे भी हैं, जो बिना खाना खाए भी अपनी पूरी जिंदगी सूर्य की ऊर्जा पर टिके रहते हैं।

> छठ में हम जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जल या आपः का एक अर्थ प्रेम भी है। जल प्रेम का प्रतीक भी है। 'आप्त' एक शब्द है, जो 'आपः' से बना है। आप्त का अर्थ है, 'जो बहुत प्रिय हो।'

नित्य सूर्य को अर्घ्य देने से भी शरीर में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जीवन निर्वाहक सूर्य को सच्चे मन से आभार की अभिव्यक्ति करना ही छठ पूजा है। यह व्रत दर्शाता है की हम अपने अस्तित्व के लिए सूर्य के ऋणी हैं। जाति, पंथ और धन की सीमाओं को पार करते हुए, लोग इस सुंदर त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आते हैं।

श्री चित्रगुप्त पूजा (29 अक्टूबर) पर विशेष

निष्फल नहीं होती चित्रगुप्त जी की आराधना

धर्मग्रंथों में आया है कि श्री सूर्य नारायण से आरोग्य, भोले भंडारी से ज्ञान, देवी मां से ऐश्वर्य, हनुमान जी से शक्ति, कार्तिकेय जी से सैन्य सफलता, भैरव जी से निडरता और गणेश जी से मंगल व यश की कामना की जाती है। ठीक उसी प्रकार जो सभी के लेखनी की इच्छा-कामना को सहज ही पूर्ण करते हैं, उनका नाम चित्रगुप्त है। ऐसे तो चित्रांश सहित कितने ही जन देव श्री चित्रगुप्त की नित्य आराधना किया करते हैं, पर हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका वार्षिक उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है।

पद्म पुराण, स्कन्द पुराण, ब्रह्मपुराण, यमसंहिता व याज्ञवलक्य स्मृति सहित कितने ही धार्मिक ग्रंथों में भगवान चित्रगुप्त का विवरण आया है। श्री चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की काया से हुई है। ब्रह्मा जी की काया से संबंध होने के कारण इस वंश को कायस्थ कहा गया। चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति की एक और कथा है कि देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उसमें कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उसी में लक्ष्मी जी के साथ श्री चित्रगुप्त जी की भी उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि श्री चित्रगुप्त जी ने ज्वालामुखी, चण्डी देवी व महिषासुर मर्दिनी की पूजा-अर्चना और साधना कर एक आदर्श कायम किया। देवलोक में श्री चित्रगुप्त की प्रतिष्ठा 'धर्मराज' के रूप में है।

ऐसे तो वैदिक काल से ही चित्रगुप्त जी की पूजा-अर्चना का भाव देखने को मिलता है, पर भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग अर्थात् गुप्तकाल से चित्रगुप्त की आराधना व्यापक रूप में होने लगी। उत्तर, दक्षिण, पूरब व पश्चिम भारत में विराजमान चार धामों के समान श्री चित्रगुप्त जी के चार धामों का भी उल्लेख आता है, जिनमें उज्जैन, कांचीपुरम, अयोध्या और पटना का नाम शामिल है। इन स्थानों पर चित्रगुप्त के प्राचीन आराधना स्थल विराजमान हैं। इसके अलावा खजुराहो, प्रयागराज, हैदराबाद, वाराणसी, भोपाल, रीवा, भरमौर, नई दिल्ली, मैहर, गुना, गया, बक्सर, भोपाल, कानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, जगन्नाथपुरी, गोरखपुर आदि नगरों में भी चित्रगुप्त मंदिर स्थापित हं। कहीं इनका स्वतंत्र देवालय है, तो कहीं देवी मां, शिवशंकर या सूर्य नारायण के मंदिर में संयुक्त रूप से विराजमान हैं। चित्रगुप्त मुक्ति, भुक्ति, मोक्ष व यश के चतुर्मणि हैं, जिनकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती।

> चार धामों के समान श्री चित्रगुप्त जी के चार धामों का भी उल्लेख आता है, जिनमें उज्जैन, कांचीपुरम, अयोध्या और पटना का नाम शामिल है। इन स्थानों पर चित्रगुप्त के प्राचीन आराधना स्थल विराजमान हैं

सामान्य रूप से चित्रगुप्त का आशय होता है, जो सबके हृदय में गुप्त रूप से उपस्थित हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने हृदय के चित्रगुप्त को जाग्रत करें, स्वयं भी पढ़ें और पूरे देश को शिक्षा के आलोक से दीप्तिमान करें। यही इस पर्व का मूल संदेश भी है जो कार्तिक शुक्ल यम द्वितीया के दिन अटूट श्रद्धा और अदम्य विश्वास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है।

डॉ. राकेश कुमार सिन्हा 'रवि'

छठ पर्व महात्मय

प्रकृति प्रेम का प्रतीक है छठ पर्व

प्रकृति आराधना का महापर्व छठ संभवतः एकमात्र त्योहार है, जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। इसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पर्व शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के चर्म रोग, यहां तक कि कुष्ठ जैसे भयानक चर्म रोग से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने भी कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य देव की आराधना की थी। छठ पूजा करने वाले व्रतियों की इस पर्व में अगाध श्रद्धा है। उन्हें इस बात में दृढ़ आस्था रहती है कि भगवान सूर्य से मांगी गई हर मुराद निश्चित पूरी होती है। लोक विश्वास यह भी है कि छठ व्रत-उपवास करने वाले परिवार में कुष्ठ या चर्म रोग नहीं होता है। इस बात की पुष्टि भविष्य पुराण भी करता है। इसकी चर्चा मार्कण्डेय पुराण में भी मिलती है।

इस पर्व में व्रती द्वारा जो साधना की जाती है, वह इतनी कठोर होती है कि मुनियों ने इस पर्व को हठयोग की संज्ञा दी है। इस व्रत को करने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे 36 घंटे तक जल भी ग्रहण नहीं करना, पूरे समय नंगे पांव चलना, रात में भूमि पर शयन करना, गृहस्थ जीवन में एक हठयोग की तरह ही है। सूर्य की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किन्तु छठ व्रत का उल्लेख भविष्य पुराण एवं महाभारत में स्पष्ट रूप से मिलता है। प्राचीन समय से चला आ रहा छठ पर्व ही ऐसा है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज में भगवान भास्कर से पुत्री प्राप्ति की कामना की जाती है। इस व्रत के गीत-'रुनकी-झुनकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दमाद' में इस प्रार्थना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मुख्य रूप से छठ में प्रकृति प्रदत्त सामग्री नीबू, गन्ना, गुड़, मूली, नारियल, केला, साठी (एक प्रकार का धान) और गेहूं से बने प्रसाद के साथ जलाशयों में खड़े हो कर पूजा की जाती है। इस पर्व में रात्रि में मिट्टी से बने हाथी की भी पूजा करने का प्रावधान है। छठ प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है।

बजरंगबली सिंह

बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो रहे सस्ते ई-रिक्शा

मुंबई। एजेंसी

तेजी से बढ़ रहे ई रिक्शा मार्केट में काइनेटिक, हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को कारोबार शुरू किए हुए दो साल से अधिक हो चुके हैं। हालांकि, इन कंपनियों को इस सेगमेंट में अपना सिक्का जमाने में अभी और समय लगेगा। इलेक्ट्रिक वीइकल्स को लेकर भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। देश में बैटरी वाले लगभग 15 लाख रिक्शा चल रहे हैं। 2015 से साइकल रिक्शा की जगह बैटरी से चलने वाले रिक्शा की बिक्री बढ़ी है। भारत में ई-रिक्शा की बिक्री 20 पर्सेंट सालाना की दर से बढ़ रही है।

असंगठित क्षेत्र के रिक्शा की ज्यादा बिक्री

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका बड़ा हिस्सा अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर से आ रहा है। इससे बड़ी कंपनियां अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हुई हैं। वाहन पोर्टल डेटा के मुताबिक, असंगठित कारोबारी एक महीने में 10,000 ई-रिक्शा की बिक्री कर रहे हैं, जबकि ऑर्गनाइज्ड कंपनियों की मासिक बिक्री 1,500-2,000 यूनिट की है।

असंगठित क्षेत्र कर रहे क्वालिटी से खिलवाड़

काइनेटिक ग्रीन एनर्जी ऐंड पावर सॉल्यूशन की सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी का कहना है, 'असंगठित कारोबारी कम क्वॉलिटी वाले ई-रिक्शा बेच रहे हैं। इनमें लेड एसिड बैटरी लगी होती है जिसे हर 6-8 महीने के बीच बदलना पड़ता है। इनके साथ कोई वॉरंटी भी नहीं होती है। इनसे सुरक्षा को खतरा है और ये चलते फिरते ताबूत की तरह हैं।'

यूपी, बिहार में ई-रिक्शा की बहुत डिमांड

ई-रिक्शा की बिक्री विशेष तौर पर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार में होती है। इन जगहों पर यह ट्रांसपॉर्टेशन के बेहतर और सस्ते जरियों में शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ई-रिक्शा की कीमत 40,000 रुपये से शुरू होती है, जबकि बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां एक लाख रुपये से अधिक के दाम पर ई-रिक्शा बेच रही हैं। कीमत में इस अंतर के चलते असंगठित क्षेत्र की ई-रिक्शा की बिक्री बढ़ी है।

ड्राइवर की आमदनी में इजाफा

पिछले साल ट्रेओ रेंज लॉन्च करने वाली महिंद्रा इलेक्ट्रिक के सीईओ महेश बाबू ने कहा, 'ई-रिक्शा लोगों के लिए किफायती और सुविधा वाला साधन है और इससे ड्राइवर की आमदनी में भी इजाफा होता है जो इस सेगमेंट के बढ़ने का प्रमुख कारण है। 2018 में ई-रिक्शा रेगुलेशन नोटिफाइड होने से पहले असंगठित क्षेत्र में लेड एसिड बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा ही बिकते थे।'

लिथियम ऑयन बैटरी वाले रिक्शा की मांग बढ़ी

महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2020 में अभी तक लिथियम-आयन बैटरी वाले ट्रेओ की केवल 1,500 यूनिट ही बेची हैं। बाबू ने कहा कि कंपनी ने लेड बैटरी से चलने वाले ई अल्फा की 15,000 यूनिट की बिक्री की है। हालांकि, चिंता लिथियम ऑयन बैटरी वाले

ई-रिक्शों को लेकर है, जिनकी बिक्री बढ़ने में कुछ वक्त लगेगा।

असंगठित क्षेत्र में भी होने लगा रजिस्ट्रेशन

हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ और सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वीइकल्स इंडिया के डायरेक्टर जनरल, सोहिंदर गिल ने बताया, 'असंगठित क्षेत्र के बहुत से कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे इन्हें बड़े मार्केट में आने का मौका मिलेगा।'

मर्सिडीज-बेंज ने नई जीएलई एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू की

मुंबई। एजेंसी

जर्मनी की कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज - बेंज ने अपनी नई 'जीएलई ' एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की। इस एसयूवी को अगले साल की शुरुआत में भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने बयान में दावा किया कि उसने धनतेरस पर ग्राहकों को 600 कारों की आपूर्ति भी की है। कंपनी ने कहा कि जीएलई के लिए जबर्दस्त मांग को देखते हुए मर्सिडीज ने इस एसयूवी के मौजूदा संस्करण को बाजार में पेश करने की योजना से तीन महीने पहले ही बेच दिया और अब नई पीढ़ी की जीएलई के लिए बुकिंग शुरू की है। इसमें कहा गया है कि नई जीएलई एसयूवी को ऑटो एक्सपो 2020 से पहले भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि मर्सिडीज ने 13,000 जीएलई कारों की अब तक बिक्री की है। कंपनी ने कहा कि त्योहारी मौसम में मर्सिडीज - बेंज वाहनों की अच्छी खासी मांग देखी गई। विशेष रूप से दिल्ली - एनसीआर , पंजाब , मुंबई , पुणे और गुजरात में मांग ज्यादा रही। धनतेरस के दिन ' रिकॉर्ड ' 600 कारों की बिक्री की गई , जिसमें से करीब 50 प्रतिशत (250 इकाइयों से अधिक) की आपूर्ति दिल्ली - एनसीआर में की गई।

नई टेक्नॉलजी को समझने के लिए दोबारा स्टूडेंट बन रहे कंपनियों के टॉप अधिकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन फार्मेसी 1एमजी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तन्मय सक्सेना एक महीना पहले फिर से स्टूडेंट बन गए। उन्होंने 'AI फॉर एब्रीवन' कोर्स के लिए एजुकेशन टेक्नॉलजी प्लैटफॉर्म कोर्सेरा पर साइन-अप किया। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (ई) से जुड़ी काफी जानकारी मौजूद होने और बिजनस में इस टेक्नॉलजी के बढ़ते महत्व के कारण सक्सेना ने इसे सीखने का फैसला किया। नए बिजनस मॉडल को चलाने और वर्कप्लेस में बदलाव के लिए AI के अलावा मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डेटा ऐनालिटिक्स जैसी उभरती टेक्नॉलजी की जरूरत बढ़ रही है। इसके चलते अब 12-15 साल के अनुभव वाले सीनियर एग्जिक्यूटिव नए स्किल को सीखने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों के ऐंध के सामने सबसे मुख्य सवाल यह है कि कैसे अपनी लॉन्ग-टर्म बिजनस स्ट्रैटिजी को मौजूदा AI कैपेबिलिटी

के साथ जोड़ा जाए। 12 साल से ज्यादा अनुभव वाले सीनियर प्रफेशनल्स के बीच ग्रेट लर्निंग की ओर से कराए एक सर्वे करीब 70 पर्सेंट प्रफेशनल्स ने माना कि उनकी कंपनी के बिजनस रोडमैप में AI की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। उनका कहना था कि वे AI के बारे में कुछ जानकारी के बजाय उसकी थिअरी और टूल्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। ग्रेट लर्निंग के को-फाउंडर हरि नायर ने बताया, 'हमारे डेटा साइंस, ऐनालिटिक्स, AI और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम के लिए इनक्वायरी करने वाले सीनियर प्रफेशनल्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन प्रोग्राम को सीखने वाले करीब 30 पर्सेंट स्टूडेंट, सीनियर प्रफेशनल्स हैं।' ग्रेट लर्निंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साथ मिलकर 'AI फॉर लीडर्स' के नाम से बिजनस लीडरों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें कस्टमर्स के साथ बातचीत और ऑपरेशंस में सुधार के लिए एआई और डेटा का इस्तेमाल सिखाया जाता है। प्रोग्राम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सेशन होंगे, जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। नायर ने बताया, 'हम सर्विसेज और प्रॉडक्ट टेक्नॉलजी कंपनियों, कंसल्टिंग फर्मों, ई-कॉमर्स कंपनियों के अलावा ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर और बैंकिंग सेक्टर के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स में भी नई तकनीक के लिए दिलचस्पी देख रहे हैं।' अन्य एजुकेशन टेक्नॉलजी प्लैटफॉर्म भी सीनियर प्रफेशनल्स इस ट्रेंड को देखकर अपने कंटेंट को सीनियर प्रफेशनल्स के अनुसार ढाल रहे हैं। इस साल की शुरुआत में Udemy ने एक एग्जिक्यूटिव ब्रीफिंग कोर्स शुरू किया था। इसमें सीनियर लीडर्स को AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि उसके कस्टमर्स में विप्रो और टेक महिंद्रा के कई एग्जिक्यूटिव शामिल हैं।

घट सकते हैं कैंसर और दिल के रोगों की दवाओं के दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दिए जानेवाले कुछ ऐंटीबायॉटिक और दवाओं का दाम घट सकता है। सरकार जल्द जरूरी दवाओं की लिस्ट अपडेट करने वाली है और उनमें से कुछ को वह प्राइस कंट्रोल वाली दवाओं की सूची में डाल सकती है। पहले वाली व्यवस्था के उलट अब सभी जरूरी दवाएं प्राइस कंट्रोल वाली लिस्ट में नहीं आएंगी।

NLEM लेगी फैसला

दवाओं की शॉर्ट लिस्टिंग करने का जिम्मा स्टैंडिंग नैशनल कमिटी ऑन मेडिसिंस को दिया गया है। नैशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस (NLEM) की 4 नवंबर को मीटिंग होने वाली है जिसमें संबंधित पक्ष अपने विचार जाहिर करेंगे। यह काम NLEM को अपडेट और फाइनल किए जाने से पहले होगा। मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सेक्रटरी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव की अध्यक्षता वाली कमिटी यह तय करेगी कि कौन-सी दवाएं समुचित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।

गैरप्रभावी दवाएं होंगी लिस्ट से बाहर

सरकार के एक सीनियर अफसर ने कहा, 'मीटिंग में कैंसर और दिल की बीमारियों में मरीजों को इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं की शॉर्टलिस्टिंग करने पर विचार किया जाएगा क्योंकि इन कैटिगरीज में बहुत से ड्रग डिवेलपमेंट हुए हैं। एक्सपर्ट्स के लिए ऐंटीबायॉटिक को लेकर विषाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता बनने से रोकना प्राथमिकता वाला मसला है। जो दवाएं भारत में मरीजों पर प्रभावी नहीं रह गई हैं, उन्हें NLEM से बाहर निकाला जाएगा और नई दवाओं को शामिल किया जाएगा।'

दवाओं का प्राइस कंट्रोल

NLEM को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रटरी प्रीति सूदन और डिपार्टमेंट ऑफ फामास्युटिकल्स में सेक्रटरी पी डी वघेला वाली दूसरी कमिटी के पास भेजा जाएगा जो यह फैसला करेगी कि किस दवा को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाना है। मौजूदा व्यवस्था में सभी जरूरी दवाएं अपने आप प्राइस कंट्रोल वाली दवाओं में शामिल हो जाती हैं। पुरानी व्यवस्था में हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्राइस रेगुलेशन के दायरे में आने वाली दवाओं की सूची तैयार की थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के शेड्यूल 1 में शामिल करा दिया था। इसके बाद नैशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस शेड्यूल में शामिल दवाओं के मूल्य निर्धारण का काम किया था।

दवाओं पर क्या है मौजूदा नियम

NLEM में शामिल दवाओं और डिवाइसेज NPPA की तरफ से तय की गई कीमत पर ही बेची जा सकती हैं जबकि नॉन शेड्यूल लिस्ट वाली दवाओं के दाम में हर साल 10% की बढ़ोतरी करने की इजाजत है। NLEM के लिए स्टेकहोल्डर्स की पहली मीटिंग जुलाई में हुई थी और उसमें दवा कंपनियों, फार्मा लॉबी ग्रुप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल थे। एक्सपर्ट्स से कैंसर, दिल की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं, पेनसिलिन प्रिपरेशन पर फीडबैक, ऐंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर जानकारी मांगी गई थी और NLEM 2015 की समीक्षा कराई गई थी। NLEM की हर तीन साल पर समीक्षा होती है।

रिजर्व बैंक के सोना बेचने वाली खबर पर आरबीआई ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोना बेचने की खबर पर सफाई जारी करते ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने हाल में 30 सालों में पहली बार अपने गोल्ड रिजर्व से सोने की बिक्री की है। आरबीआई ने रविवार को ट्वीट कर इन खबरों को गलत बताया है। रिजर्व बैंक ने मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई ने सोना बेचने और उसका व्यापार नहीं किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (ेएए) में दर्शाए गए मूल्य में उतार-चढ़ाव मासिक से साप्ताहिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण होता है और यह सोने और विनिमय दरों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है।

गौरतलब है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि आरबीआई ने कुल 1.15 अरब का सोना बेचा है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकीय पूरक के डाटा ऐनालिसिस से पता चला है कि इसने अपने बिजनेस ईयर की शुरुआत वाले महीने यानी जुलाई से 5.1 अरब का सोना खरीदा है और लगभग 1.15 अरब का सोना बेचा है।

धनतेरस पर देशभर में सोने की बिक्री 25 फीसदी घटी

महंगी धातुओं की खरीदारी के शुभ-मुहूर्त धनतेरस पर इस साल देशभर में करीब 30 टन सोने की बिक्री हुई, जो कि उम्मीद से ज्यादा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने यह जानकारी दी। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल बिक्री 25 फीसदी कम रही है। आईबीजेए के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि विगत वर्षों के दौरान धनतेरस पर भारत में करीब 40 टन सोने की खरीददारी होती थी, लेकिन इस साल सोने का दाम ऊंचा रहने और बाजार में तरलता की कमी के कारण लिवाली 20 टन के आसपास रहने का अंदेशा जताया गया था। इस साल सोने की लिवाली पिछले साल से 25 फीसदी कमजोर रही।

ऊंचे दाम से उत्साह ठंडा

पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने का भाव घरेलू बाजार में करीब सात हजार रुपये प्रति 10 ग्राम ऊंचा है। सोना महंगा होने के कारण खरीदारी नरम रही है। मेहता ने हालांकि, कहा कि कुछ दिन पहले इतनी खरीददारी होने का भी अनुमान नहीं था, क्योंकि घरेलू सराफा बाजार में ऊंचे भाव पर पीली धातु में मांग कमजोर देखी जा रही थी।

नकदी का अभाव

ऊंचे दाम के साथ उपभोक्ताओं के पास नकदी का अभाव भी उन्हें जमकर खरीददारी करने से रोक रहा है। मेहता का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव इस साल तेज रहने और भारत में महंगी धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ जाने के कारण घरेलू सराफा बाजार में दाम काफी उंचा हो गया है, जबकि लोगों के पास नकदी का अभाव है। इसलिए त्योहारी सीजन के आरंभ में सोने में मांग कमजोर देखी जा रही थी। हालांकि, विगत तीन-चार दिनों में खरीददारी ने जिस प्रकार जोर पकड़ा है उससे इस धनतेरस पर सोने की लिवाली उम्मीद से अधिक रही। इस माह की शुरुआत में मेहता ने कहा था कि कमजोर मांग के कारण इस साल लगता है कि धनतेरस पर देशभर के सराफा बाजार में बमुश्किल से 20 टन सोना बिक पाएगा।

बैंक में निवेश से मोहभंग

केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि पीएमसी बैंक में घोटाले उजागर होने के बाद बैंकिंग स्कीमों में निवेश के प्रति छोटे निवेशकों का विश्वास कम हुआ है, जिससे सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं में निवेश के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। उनका कहना है कि यही वजह से है कि उपभोक्ताओं ने उद्योग की उम्मीद से ज्यादा सोना खरीदा है और यह बात अलग है कि पिछले साल के मुकाबले खरीददारी कम रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में सोना निवेश का बेहतर विकल्प बना हुआ है। एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट करेंसी एंड एनर्जी रिसर्च अनुज गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय मुद्रा रुपये में डॉलर के मुकाबले मजबूती आई है, जिससे घरेलू सराफा बाजार में महंगी धातु की मांग को सपोर्ट मिला है। हालांकि सोने में इस साल बेहतर रिटर्न मिलने से पीली धातु में निवेश मांग बढ़ी है।

घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हालांकि बीते सत्र में शुक्रवार को सोने का दिसंबर अनुबंध 77 रुपये की कमजोरी के साथ 38,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ लेकिन पिछले साल धनतेरस के मुकाबले भाव काफी उंचा है जब एमसीएक्स पर सोने की कीमत 31,702 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद सोने का आयात कम करने के मकसद से नवगठित सरकार ने जुलाई में चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करते हुए महंगी धातुओं पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया जिससे देश में सोना महंगा हो गया है।

इस साल दिवाली पर उम्मीद से भी ज्यादा बिका सोना, देशभर में 30 टन गोल्ड की हुई बिक्री

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने का भाव घरेलू बाजार में करीब सात हजार रुपये प्रति 10 ग्राम ऊंचा है। सोना महंगा होने के कारण खरीदारी नरम रही है। मेहता ने हालांकि, कहा कि कुछ दिन पहले इतनी खरीददारी होने का भी अनुमान नहीं था, क्योंकि घरेलू सर्राफा बाजार में ऊंचे भाव पर पीली धातु में मांग कमजोर देखी जा रही थी।

महंगी धातुओं की खरीददारी के शुभ-मुहूर्त धनतेरस पर इस साल देशभर में करीब 30 टन सोने की बिक्री हुई, जो कि उम्मीद से ज्यादा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने यह जानकारी दी। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल बिक्री 25 फीसदी कम रही है। आईबीजेए के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि विगत वर्षों के दौरान धनतेरस पर भारत में करीब 40 टन सोने की खरीददारी होती थी। बता दें कि हर साल धनतेरस पर औसतन 40 टन सोना बिकता है। इस साल 20 टन सोना बिकने की उम्मीद थी।

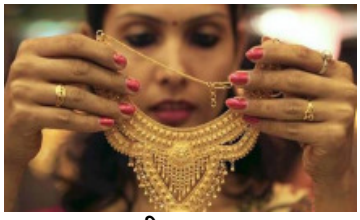

नकदी का आभाव

अंतरराष्ट्री बाजार में सोने का भाव इस साल तेज रहने और भारत में महंगी धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ जाने के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में दाम काफी उंचा हो गया है, जबकि लोगों के पास नकदी का आभाव है। मेहता का कहना है कि इसलिए त्योहारी सीजन के आरंभ में मांग कमजोर देखी जा रही थी। तीन-चार दिनों में खरीददारी ने जोर पकड़ा जिससे धनतेरस पर खरीद उम्मीद से अधिक रही है।

बैंक में निवेश से मोहभंग

केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि पीएमसी बैंक में घोटाले उजागर होने के बाद बैंकिंग स्कीमों में निवेश के प्रति छोटे निवेशकों का विश्वास कम हुआ हैं। जिससे सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं में निवेश के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। उनका कहना है कि यही वजह है कि उपभोक्ताओं ने उद्योग की उम्मीद से ज्यादा सोना खरीदा है।

डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से सोने को लाभ

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट करेंसी एंड एनर्जी रिसर्च अनुज गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय मुद्रा रुपए में डॉलर के मुकाबले मजबूती आई है। जिससे घरेलू सर्राफा बाजार में महंगी धातु की मांग को सपोर्ट मिला है। हालाकि सोने में इस साल बेहतर रिटर्न मिलने से पीली धातु में निवेश की मांग बढ़ी है। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हालांकि बीते सत्र शुक्रवार को सोने का दिसंबर अनुबंध 77 रुपए की कमजोरी के साथ 38,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ लेकिन पिछले साल धनतेरस के मुकाबले भाव काफी उंचा है जब एमसीएक्स पर सोने की कीमत 31,702 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

मुहूर्त ट्रेडिंग

दीपावली की शाम एक घंटे में शहरवासियों ने किया 100 करोड़ का निवेश

मुंबई। दीपावली पर रविवार शाम को शेयर मार्केट में एक घंटे होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में शहर के लोगों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों का कहना है कि यह रकम पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। दीपावली पर रविवार की शाम एक घंटे के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग की गई। इसे मुहूर्त ट्रेडिंग बताया गया। इस ट्रेडिंग का समय शाम 6:15 से 7:15 बजे तक का रहा। शेयर ब्रोकर शरद अग्रवाल ने बताया कि दीपावली की मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट के सभी एक्सचेंज खुलते हैं। जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीएक्स) में सोना, चांदी, निकिल, कॉपर, कच्चे तेल, मसाला आदि की खरीद बिक्री की गई। शरद अग्रवाल ने बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार की चाल सकारात्मक रहती है। ऐसे में सौदा खरीदने-बेचने वालों के नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। शेयर ब्रोकर अंशुमान मालवीय ने बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग में वर्ष 2018 में शहर के लोगों ने लगभग 50 करोड़ का निवेश किया था। इस बार उम्मीद है कि यह आंकड़ा लगभग 100 करोड़ के आसपास रहा। बाजार की सकारात्मक चाल का लाभ ट्रेडिंग करने वालों को मिलता है। बाजार भी बढ़त के साथ खुलता और बंद होता है।

दक्षिण कोरिया से रबड़ के निर्यात पर सब्सिडी की जांच

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने दक्षिण कोरिया से एक विशेष प्रकार के रबड़ के निर्यात पर कथित रूप से सब्सिडी दिए जाने की जांच शुरू कर दी है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि इससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने जांच शुरू कर दी है। जांच के जरिये यह पता लगाया जाएगा कि क्या दक्षिण कोरिया के स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ के निर्यात के सब्सिडी कार्यक्रम से घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है। डीजीटीआर ने कहा कि इंडियन सिंथेटिक रबड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निदेशालय के समक्ष इस बारे में शिकायत की थी। डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार उसे इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस रबड़ के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिपूर्ति सब्सिडी दी जा रही है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह के सब्सिडी वाले आयात से घरेलू उद्योग को चोट पहुंच रही है और भविष्य में उसे और नुकसान का अंदेशा है। निदेशालय अपनी जांच के जरिये कथित सब्सिडी के प्रभाव का आकलन करेगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि दक्षिण कोरिया द्वारा दी जा रही सब्सिडी से घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है तो डीजीटीआर प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।